विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर एक अतिरिक्त मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया उत्तर बिहार में भारतमाला परियोजना के तहत एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने पर विचार करें। यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सड़क, रेलवे और संभावित जलमार्गों सहित कई परिवहन विधाओं के संयोजन का एक केंद्र बनेगा, जो माल के सुचारू रूप और प्रभावी परिवहन को सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही इसमें अत्याधुनिक वेयर हाउसिंग और एकीकृत कस्टम क्लियरेंस सुविधाएं दी जाएंगी। उत्तर बिहार की नेपाल सीमा से निकटता और कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से सामरिक संपर्क सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इसके साथ ही यह कृषि निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा और देश भर के विभिन्न बिंदुओं से संपर्क स्थापित करने में मदद करेगा। उपसभापति महोदय, मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Sanjay Kumar Jha: Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar), Dr. John Brittas (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Demand to make recruitment process for the posts of Post Master and Gramin Dak Sewak in Uttarakhand on the basis of state level cadre

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में एक महत्वपूर्ण विषय रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पिछले दिनों संचार विभाग द्वारा उत्तराखंड में अनेक पोस्ट मास्टर्स तथा डाक सेवकों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, इन नियुक्तियों में देश के अनेक बेरोजगारों को नियुक्ति दी गई, परंतु अनेक युवाओं को उत्तराखंड के जटिल पहाड़ी स्वरूप एवं भाषा बोली की दिक्कतों के कारण अपने स्थल पर नियुक्ति नहीं दी गई। महोदय, पूर्व में ये नियुक्तियाँ राज्य के मंडल स्तर कैडर के आधार पर होती थीं तथा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलता था, जो उस क्षेत्र की भाषा और बोली को समझते थे तथा ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिलता था। महोदय, आज देश के सभी डाकघरों को जिस प्रकार से अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है, वह कदम स्वागतयोग्य है। उत्तराखंड में भी तकनीकी जानकारी रखने वाले अनेक युवा हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था आज भी मनी ऑर्डर पर केंद्रित है, अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के विषय पर पोस्ट मास्टर्स तथा ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति अवश्य पारदर्शी हो, परंतु इसका नियुक्ति कैडर पूर्ववत् ही रखा जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Mahendra Bhatt: Shrimati Maya Naroliya

(Madhya Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Demand for expediting railway projects in Karnataka

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to highlight the stalled railway projects in Karnataka's South Western Railway (SWR) Zone, including Hubballi, Bengaluru and Mysore. Despite approval of 13 projects, there has been very little progress. Sir, the projects which are not even started include Dharwad-Belagavi direct rail line; Gadag-Yalavigi rail line which was approved in 2016-17, but still it is only on paper. Hubballi-Ankola rail project, which could connect the Bayaluseeme region. Then, Shivamogga-Shikaripura-Ranebennur project; Hubballi-Shirsi-Talaguppa rail line and Davangere-Tumakuru railway project.

Additionally, the following new railway line proposals, which could transform connectivity in the region, have also seen little progress: Gadag (Talikoti) — Wadi; Tumakuru-Davangere (via Chitradurga); Tumakuru-Rayadurg (via Kalyanadurga); Bagalkot-Kudachi; Shivamogga- Shikaripura — Ranebennur; Belagavi — Dharwad (via Kittur); Kadur — Chikkamagaluru — Hassan; Malagur — Palasamudra; Hassan — Bengaluru (via Shravanabelagola); Hubballi — Ankola; and Gadag — Yalavigi.

Also, the Mangaluru Railway Zone is divided among Palakkad, Konkan and South Western Railways and although 75 per cent of the revenue for Palakkad Division comes from Mangaluru, the city does not receive adequate railway infrastructure and facilities in return. This imbalance must be rectified.

Sir, these projects are not impossible to implement. The primary roadblock remains the lack of coordination between the State and railway authorities. I urge the Railway Ministry to take immediate action on these pressing issues. The people of Karnataka deserve better connectivity, efficient transport, and equitable railway development.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri G.C. Chandrashekhar: Shri A. A. Rahim (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Dr. John Brittas (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Dr. V. Sivadasan (Kerala).

Mananiya Shrimati Sumitra Balmik, "Demand for establishment of a Lithium-Ion Battery Recycling Research Centre and Hub in Madhya Pradesh."